सरकारी क्षेत्र के क्रमशः 78 एवं 80 उपक्रमों ने लाभांश का भुगतान किया। अन्य जानकारी इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

	1995-96	1996-97
भुगतान किए गए लाभांश की राशि	2205	3080
पूंजीनिवेश	100917	112321
भुगतान किया गया ब्याज	6204	7903

औद्योगिक मंदी से प्रभावित हुआ सेवा क्षेत्र

821. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजकल भारतीय उद्योग भीषण मंदी के दौर से गुजर रहा है और कई उद्योग और कारखाने या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) क्या इस औद्योगिक मंदी के कारण सेवा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है और उद्योग की तरह इस क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर कम हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न उद्योगों और विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कितने प्रतिशत गिरावट आई है; और

(घ) सरकार द्वारा उद्योग और सेवा क्षेत्र की उबारने हेतु और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान कुल औद्योगिक विकास क्रमशः 5.6 प्रतिशत तथा 6.6 प्रतिशत था। चालू वर्ष अप्रैल-सितम्बर, 1998 के दौरान विकास की दर पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.0 प्रतिशत की तुलना में 3.6 प्रतिशत है। किंतु, वाणिज्यिक एककों की संख्या में वृद्धि हुई है। रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अनुसार सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक स्थापनाओं की संख्या, जो 31 मार्च, 1996 को 2,71,466 थी, 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 2,77,553 हो गई है। विकास आयुक्त, लघु उद्योग से उपलब्ध सूचना के अनुसार लघु क्षेत्र में भी एककों की संख्या 1996-97 के 28.57 लाख से बढ़कर 1997-98 में 30.40 लाख एकक हो गई है।

(ख) और (ग) विभिन्न उद्योगों तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार तथा प्रतिशत परिवर्तन निम्नानुसार है:—

रोजगार (लाख में, 31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं)

उद्योग/सेवाएं	1994	1995	1996
विनिर्माण	64.14	66.21 (3.2)	66.58 (0.6)
विद्युत, गैस तथा जल	9.78	10.07 (2.9)	9.86 (-2.1)
निर्माण	12.18	12.18 (—)	12.06 (-1.0)
थोक तथा खुदरा व्यापार और भोजनालय तथा होटल	4.62	4.76 (1.0)	4.81 (1.0)
परिवहन, भंडारण तथा संचार	31.40	31.57 (0.5)	29.96 (-5.1)
वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यापार सेवाएं	15.55	16.56 (6.5)	16.15 (2.5)
सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं	110.63	112.95 (2.1)	112.01 (-0.8)

(घ) औद्योगिक विकास में कमी को रोकने के लिए सरकार ने 1998-99 की बजट अवधि में तथा उसके बाद औद्योगिक विकास को तीव्र करने तथा पुनरूज्जीवित करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किये हैं। बजट में घोषित उपायों के पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) कोयला तथा लिग्नाइट, पैट्रोलियम रिफाइनिंग तथा चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना,

(2) अनिवासी भारतीयों द्वारा समग्र निवेश की सीमा में 5% से बढ़ाकर 10% करना,

(3) घरेलू उद्योगों के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सीमा शुल्कों की विशेष अतिरिक्त शुल्क शुरू करके प्रशुल्क ढांचे को युक्तियुक्त बनाना,

(4) उप ऊर्जा, परिवहन तथा दूर संचार के लिए योजनागत परिव्यय को वर्ष 1997-98 के 45,252 करोड़ रु० (संशोधित अनुमान) के मुकाबले में वर्ष 1998-99 के 61,146 करोड़ रु० (बजट अनुमान) करके 35% तक बढ़ाया गया।

(5) विद्युत प्रशुल्कों को युक्तियुक्त करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य विद्युत विनियमन आयोग स्थापित करना,

(6) शहरी भूमि परिसीमन तथा विनियमन अधिनियम को रद्द करना जिससे निर्माण संबंधी गतिविधियां तेज होंगी और सीमेंट, इस्पात इत्यादि जैसी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

उद्योग को और गति देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित और उपाय घोषित किए हैं:—

(1) निर्यात में वृद्धि को पुनरूज्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई।

(2) सरकार ने हाल ही में निवेश में वृद्धि तथा पूंजी बाजार को पुनरूज्जीवित करने के लिए शेयरों की पुनः खरीद तथा अन्तः कार्पोरेट ऋण की अनुमति दी।

(3) औद्योगिक गतिविधियों को शीघ्र बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई जिससे ब्याज दरों की वृद्धि से बचाव हुआ है।

(4) सरकार द्वारा तीन बड़े फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटियां दी गई हैं जिससे वित्तीय परिसमापन की आशा है और इस प्रकार मौलिक तथा अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

(5) 28,000/- करोड़ रु० की लागत से 7,000 कि०मी० के छः मार्गीय राजमार्ग शुरू किये जायेंगे।

(6) सरकार बीमा क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की अनुमति देने के लिए सहमत हो गई है। बीमा क्षेत्र के खुल जाने से अवस्थापरक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्त मुहैया होगा।

(7) सरकार औद्योगिक क्षेत्र की पुर्नस्थापना की जरूरत के प्रति जागरूक है और इन क्षेत्रों के सम्मुख आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए नीतिगत उप रुकावटों पर सिफारिश करने के लिए 4 कार्यदल-इस्पात, पूंजीगत माल, व्यावसायिक वाहन तथा सीमेंट के लिए गठित किये हैं। इन कार्यदलों ने अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं। सरकार ने इस्पात निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सात निविष्टियों को विशेष सीमा शुल्क से छूट हेतु पहले ही एक अधिसूचना जारी कर दी है। अन्य क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत घोषणाएं शीघ्र ही किये जाने की आशा है।

Performance of PSUs

822. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of Central Public Sector Units in the country, State-wise;

(b) the number of PSUs making profit/loss separately, State-wise;

(c) the reasons for their sickness;

(d) the total number of workers in the sick PSUs; and

(e) the steps Government have taken for the revival of sick PSUs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): (a) to (d) There were 236 Central Public Sector Undertakings in operation as on 31.3.97 till which period the information is available of which 60 were sick enterprises registered with BIFR. In hese units there were 3.87 lakh